भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3495
जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन में बैंकिंग अभिकर्ताओं की भूमिका

†3495. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकिंग अभिकर्ता (बीसी) ग्रामीण, दूरस्थ, जनजातीय और अल्पसेवित क्षेत्रों में बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अपर्याप्त पारिश्रमिक, सेवा की कमी और सामाजिक सुरक्षा और मध्यस्थ एजेंसियों के माध्यम से संलग्नता के कारण बैंकिंग संवाददाताओं द्वारा बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बैंक-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बीसी वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने बीसी ने कार्य छोड़ दिया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं पर इस प्रकार के व्यवधान के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का सीधे बैंक द्वारा संलग्नता, सुनिश्चित पारिश्रमिक, उचित कमीशन, सामाजिक सुरक्षा, मध्यस्थ एजेंसियों के विनियमन और एक व्यापक नीतिगत ढांचे के माध्यम से बीसी की सेवा शर्तों में सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): कारोबार प्रतिनिधि(बीसी) विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ, जनजातीय और अल्पसेवित क्षेत्रों में घर-घर तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विगत कुछ वर्षों में, कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दायरे में काफी विस्तार हुआ है और वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य बैंकिग सेवाओं के अलावा लेन-देन सम्बन्धी सेवाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता खोलना, जमा जुटाना, संभावित जरूरतमंद लोगों को ऋण देना, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली, सूक्ष्म बीमा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, आवर्ती जमा सेवाएं आदि शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के उपयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) को नियुक्त करने के लिए नीति तैयार करते हैं।

बैंक आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का भी चयन करते हैं और चयनित कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधि (सीबीसी) इसके बदले में बैंकों द्वारा सुझाए गए स्थानों पर अलग-अलग कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) को तैनात करता है । पारिश्रमिक, काम पर लगाना, निरंतरता, बर्खास्त करना और किसी भी संविदात्मक लाभ सहित सेवा शर्तें, संबंधित व्यक्ति, कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधि (सीबीसी) और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के बीच किए गए संविदा की शर्तों द्वारा अभिशासित होती हैं। तथापि, कारोबार प्रतिनिधि निगरानी समिति के माध्यम से कारोबार प्रतिनिधियों की कार्य-पद्धति और विभिन्न अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी की जाती है।

समय-समय पर कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के कामकाज और विभिन्न अन्य पहलुओं की आवधिक निगरानी की जाती है, जिसमें पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, शास्तियां, प्रमाणन, नियोजन सम्बन्धी क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। तदनुसार, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जो कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की कार्य-पद्धति को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) को कमीशन/शुल्क का भुगतान करते हैं, जिसकी दर और मात्रा की आवधिक समीक्षा की जाती है। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) कारोबार की मात्रा और व्यक्तिगत बैंक की पारिश्रमिक नीतियों के आधार पर कमीशन अर्जित करते हैं।

जन धन दर्शक (जेडीडी) जीआईएस ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 17.36 लाख कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बैंकिंग प्रणाली के लिए अंतिम व्यक्ति तक सेवा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। विगत तीन वर्ष के दौरान काम पर लगे हुए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का राज्यवार और बैंक श्रेणी-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है। विगत तीन वर्ष के दौरान हटाए गए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के बैंक-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडों का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

****

अनुबंध

'वित्तीय समावेशन में बैंकिंग अभिकर्ताओं की भूमिका के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

कारोबार प्रतिनिधि(बीसी) की राज्यवार संख्या

क्रम. सं.	राज्य का नाम	मार्च,2024	मार्च,2025	मार्च,2026	जून,2026
1	आंध्र प्रदेश	37,536	41,939	49,723	49,944
2	अरुणाचल प्रदेश	1,224	1,286	1,304	1,314
3	असम	25,498	29,268	50,314	50,569
4	बिहार	1,29,981	2,20,058	2,30,141	2,30,327
5	छत्तीसगढ़	28,880	50,409	52,406	52,761
6	गोवा	1,098	1,186	1,260	1,260
7	गुजरात	37,984	59,519	63,112	63,407
8	हरियाणा	18,860	22,342	23,554	23,568
9	हिमाचल प्रदेश	4,420	4,929	4,890	4,909
10	झारखंड	38,049	45,758	79,557	81,424
11	कर्नाटक	30,595	56,805	57,139	57,199
12	केरल	9,036	9,477	9,268	9,317
13	मध्य प्रदेश	1,04,844	1,72,021	1,81,577	1,85,018
14	महाराष्ट्र	86,459	1,41,593	1,57,349	1,58,544
15	मणिपुर	1,332	1,408	1,435	1,443
16	मेघालय	1,529	1,564	1,570	1,570
17	मिजोरम	538	631	628	629
18	नागालैंड	489	517	514	519
19	ओडिशा	29,324	34,468	49,848	53,305
20	पंजाब	17,816	18,859	19,552	19,774
21	राजस्थान	60,712	1,09,168	1,08,872	1,09,405
22	सिक्किम	150	173	167	169
23	तमिलनाडु	28,064	33,578	34,505	34,586
24	तेलंगाना	32,781	38,693	44,033	44,058
25	त्रिपुरा	1,960	2,270	2,320	2,325
26	उत्तर प्रदेश	2,05,178	3,37,974	3,59,499	3,62,515
27	उत्तराखंड	6,097	7,263	9,344	9,528
28	पश्चिम बंगाल	48,434	63,329	92,386	1,07,355
29	अंडमान और निकोबार	26	27	27	27
30	चंडीगढ़	235	243	543	543
31	दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	499	501	510	510
32	दिल्ली	11,328	13,352	14,072	14,134
33	जम्मू और कश्मीर	2,993	3,431	3,911	3,644
34	लद्दाख	164	164	103	105
35	लक्षद्वीप	3	3	3	3
36	पुडुचेरी	256	284	332	333
कुल		10,04,372	15,24,490	17,05,768	17,36,041

बैंक प्रकार-वार कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) की संख्या

क्रम. सं.	बैंक का प्रकार	मार्च,2024	मार्च,2025	मार्च,2026	जून, 2026
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2,20,671	2,59,347	2,77,676	2,81,382
2	निजी क्षेत्र के बैंक	32,173	30,422	29,774	30,765
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	61,879	65,682	65,459	65,592
4	भुगतान बैंक	6,87,211	11,67,193	13,30,937	13,56,379
कुल		10,04,372	15,24,490	17,05,768	17,36,041

स्रोत: जेडीडी ऐप